

जबलपुर, शुक्रवार 10 जुलाई 2026

login : www.haribhoomi.com

बिना वैध अनुमति और मानकों के संचालन के आरोप, विभागीय निगरानी पर सवाल बिना पंजीयन चल रहे निजी अस्पताल और पैथोलॉजी लैब नियमों की अनरेखी, मरीजों की जिंदगी से खिलवाड़!

हरिभूमि न्यूज » छिंदवाड़ा, मनीष गड़करी

जिले में स्वास्थ्य सेवाओं की आड़ में बड़ा खेल चलने की आशंका ने चिकित्सा विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आरोप हैं कि जिले के कई निजी नर्सिंग होम एवं अस्पतालों में बिना वैध पंजीयन, बिना आवश्यक अनुमति और निर्धारित मानकों का पालन किए पैथोलॉजी लैब संचालित की जा रही हैं। यदि शिकायतें सही पाई जाती हैं तो यह मामला केवल नियमों के उल्लंघन तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि सीधे-सीधे मरीजों के स्वास्थ्य और जीवन से जुड़े गंभीर खतरे का विषय बन जाएगा। सूत्रों से प्राप्त जानकारी एवं स्थानीय स्तर पर सामने आई शिकायतों के अनुसार कई निजी अस्पताल अपने परिसर में पैथोलॉजी जांच की सुविधा उपलब्ध तो करा रहे हैं, लेकिन इन लैबों के संचालन के लिए आवश्यक वैधानिक पंजीयन, मान्यता एवं अन्य अनिवार्य औपचारिकताओं का पालन नहीं किया गया है। ऐसे में यह सवाल उठना

नियम कहते हैं पहले पंजीयन, फिर संचालन

स्वास्थ्य क्षेत्र के जानकारों का कहना है कि किसी भी पैथोलॉजी लैब का संचालन निर्धारित नियमों, योग्य विशेषज्ञों की उपलब्धता, आवश्यक उपकरणों, गुणवत्ता नियंत्रण व्यवस्था तथा संबंधित विभाग से विधिवत पंजीयन प्राप्त करने के बाद ही किया जा सकता है। इन नियमों का उद्देश्य केवल औपचारिकता पूरी करना नहीं बल्कि मरीजों को सही जांच रिपोर्ट उपलब्ध कराना है।यदि बिना वैध अनुमति के लैब संचालित हो रही हैं तो यह न केवल नियामक व्यवस्था की विफलता दर्शाता है बल्कि मरीजों के उपचार को भी प्रभावित कर सकता है। गलत या संदिग्ध जांच रिपोर्ट के आधार पर मरीज को गलत दवा, अनावश्यक इलाज या गंभीर बीमारी की गलत पहचान जैसी परिस्थितियां पैदा हो सकती हैं। अभी हाल ही में चतुर्वेदी इंटेल लैबीक की शिकायत हुई है जिस पर बिना रजिस्ट्रेशन के संचालन का आरोप लगे है।

स्वास्थ्य विभाग की निगरानी पर सवाल

सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि यदि जिले में लंबे समय से ऐसी लैब संचालित हो रही हैं तो संबंधित अधिकारियों की नियमित निरीक्षण व्यवस्था आखिर कहाँ है? क्या समय-समय पर निजी अस्पतालों एवं नर्सिंग होम का निरीक्षण किया जाता है? यदि किया जाता है तो बिना पंजीयन लैब कैसे संचालित होती रही? और यदि निरीक्षण नहीं हुआ तो इसकी जिम्मेदारी किसकी तय होगी?जानकारों का कहना है कि स्वास्थ्य विभाग को प्रत्येक निजी अस्पताल में संचालित पैथोलॉजी सेवाओं का रिकॉर्ड उपलब्ध होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं है तो यह निगरानी व्यवस्था की गंभीर कमजोरी मानी जाएगी।

स्वाभाविक है कि जिन जांच रिपोर्टों के आधार पर मरीजों का इलाज किया जा रहा है, उनकी गुणवत्ता और विश्वसनीयता की जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा?

मरीजों की जेब पर भी पड़ सकता है असर

शिकायतकर्ताओं का कहना है कि कई निजी अस्पताल मरीजों को बाहर की मान्यता प्राप्त लैब में जांच कराने के बजाय अपनी ही लैब में जांच कराने के लिए प्रेरित करते हैं। यदि ऐसी लैब वैधानिक रूप से पंजीकृत नहीं हैं तो मरीजों से वसूली जाने वाली जांच राशि की वैधता पर भी प्रश्न उठता है। लोगों का कहना है कि स्वास्थ्य सेवा के नाम पर मरीजों की मजबूरी का लाभ नहीं उठाया जाना चाहिए। स्वास्थ्य विभाग के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती पूरे जिले में संचालित निजी अस्पतालों, नर्सिंग होम एवं पैथोलॉजी लैब का व्यापक सत्यापन अभियान चलाने की है। विशेषज्ञों का मानना है कि प्रत्येक संस्थान से पंजीयन प्रमाणपत्र, लाइसेंस, योग्य तकनीकी स्टाफ की जानकारी तथा उपकरणों के गुणवत्ता मानकों की जांच की जानी चाहिए। जिन संस्थानों में अनियमितताएं पाई जाएं, उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई होना आवश्यक है।

सामाजिक संगठनों ने उठाई पारदर्शिता की मांग

जिले के कई सामाजिक संगठनों एवं जागरूक नागरिकों ने मांग की है कि स्वास्थ्य विभाग जिले के सभी निजी अस्पतालों एवं नर्सिंग होम की सूची सार्वजनिक करे तथा यह भी स्पष्ट करे कि किन संस्थानों के पास वैध पंजीयन प्राप्त पैथोलॉजी लैब संचालित करने की अनुमति है। उनका कहना है कि पारदर्शिता से ही मरीजों का विश्वास कायम रहेगा और अवैध गतिविधियों पर रोक लग सकेगी। विशेषज्ञ बोले—जांच रिपोर्ट ही इलाज की नींवकिन्तु विशेषज्ञों के अनुसार आधुनिक चिकित्सा में लगभग हर गंभीर बीमारी का उपचार जांच रिपोर्ट पर आधारित होता है। यदि रक्त, मूत्र, बायोकेमिस्ट्री या अन्य पैथोलॉजिकल जांचों में त्रुटि होती है तो पूरा उपचार प्रभावित हो सकता है। इसलिए पैथोलॉजी लैब का संचालन केवल प्रशिक्षित विशेषज्ञों और निर्धारित मानकों के अनुरूप होना अत्यंत आवश्यक है। स्वास्थ्य विभाग समय-समय पर गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के दावे करता है, लेकिन यदि जिले में बिना पंजीयन लैब संचालित होने की शिकायतें सही साबित होती हैं तो यह उन दावों की वास्तविकता पर भी प्रश्नचिह्न होगा। आम नागरिकों का कहना है कि कार्रवाई केवल कागजों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि वास्तविक निरीक्षण कर दोषियों के विरुद्ध प्रभावी कदम उठाए जाने चाहिए।

वे सवाल जिनके जवाब जल्द होंगे सामने

- जिले में कुल कितनी निजी पैथोलॉजी लैब पंजीकृत हैं/कितने निजी अस्पताल अपने परिसर में पैथोलॉजी लैब संचालित कर रहे हैं? - क्या सभी लैब के पास वैध पंजीयन एवं आवश्यक अनुमति उपलब्ध है? - पिछले तीन वर्षों में स्वास्थ्य विभाग ने कितने निरीक्षण किए? - बिना अनुमति संचालन पाए जाने पर अब तक कितनी कार्रवाई हुई? - क्या मरीजों से ली गई जांच शुल्क की भी जांच होगी? - क्या पैथालॉजी लैब में एमडी डॉक्टर हैं? - इन सवालों के जवाब आने वाले समय में पूरे मामले को तत्सर्वीर स्पष्ट कर सकते हैं।

जिले में अगी तक 294.2 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज

छिन्दवाड़ा। जिले की औसत वर्षा 1059 मि.मी. है तथा जिले में अभी तक 294.2 मि.मी.औसत वर्षा दर्ज की गई है, जबकि गत वर्ष इस अवधि तक 406.7 मि.मी.औसत वर्षा दर्ज की गई थी। जिले में 09 जुलाई 2026 को प्रातः 8 बजे समाप्त 24 घंटों के दौरान 23.7 मि.मी.औसत वर्षा दर्ज की गई है।

अधिक्षक भू-अभिलेख ने बताया कि 09 जुलाई 2026 को प्रातः 8 बजे समाप्त 24 घंटों के दौरान तहसील छिंदवाड़ा में 5.2, मोहखेड़ में 9.4, तामिया में 45, अमरवाड़ा में 38.2, चौरई में 4.2, हरई में 12.4, बिछुआ में 3.4, परासिया में 21.3, जुन्नारदेव में 59.4, चांद में 0.2 और उमरेठ में 62.4 मि.मी. वर्षा दर्ज की गई है।

नशे में स्कूल पहुंचा शिक्षक, जनप्रतिनिधि की शिकायत के बाद कार्रवाई तेज वीडियो और लिखित शिकायत के आधार पर जांच शुरू, बीआरसी ने पंचनामा बनाया, शिक्षक पर निलंबन की तलवार

हरिभूमि न्यूज » परासिया

परासिया विकासखंड के एक शासकीय विद्यालय में पदस्थ शिक्षक के शराब के नशे में स्कूल पहुंचने का मामला सामने आने के बाद शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है। जनपद सदस्य की शिकायत और वीडियो सामने आने के बाद विभागीय अधिकारियों ने जांच शुरू कर दी है। मामले में संबंधित शिक्षक पर निलंबन की कार्रवाई की संभावना जताई जा रही है।जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत खिरसाइह के अंतर्गत संचालित एक शासकीय विद्यालय में गुरुवार को एक शिक्षक कथित रूप से शराब के नशे में बच्चों को पढ़ाने



पहुंचा। इसकी सूचना क्षेत्र के जनपद सदस्य सुनील अहाके की मिली तो वे तत्काल विद्यालय पहुंचे। उन्होंने शिक्षक का वीडियो बनाया और विकासखंड शिक्षा अधिकारी (बीईओ), विकासखंड

स्रोत समन्वयक (बीआरसी) तथा जिला शिक्षा अधिकारी को भेजकर कार्रवाई की मांग की। जनपद सदस्य सुनील अहाके ने 9 जुलाई 2026 को विकासखंड शिक्षा अधिकारी को लिखित शिकायत भी सौंपी।

रेत माफिया के आगे बेअसर प्रशासन! तामिया में एसडीएम के आदेशों को खुली चुनौती

गश्त और चेकिंग के दावों के बीच धड़ल्ले से हो रहा अवैध उत्खनन व परिवहन

हरिभूमि न्यूज » तामिया

तामिया क्षेत्र में रेत के अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण पर रोक लगाने के लिए प्रशासनिक स्तर पर किए जा रहे प्रयासों के बावजूद स्थिति में अपेक्षित सुधार नहीं दिख रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि राजस्व एवं खनिज विभाग की गश्त के बाद भी रेत माफिया सक्रिय हैं और नदी-नालों से अवैध रूप से रेत निकालकर विभिन्न स्थानों पर उसका भंडारण तथा निर्माण कार्यों में उपयोग किया जा रहा है।

ग्रामीणों के अनुसार क्षेत्र के कई नदी-नालों के किनारे बड़ी मात्रा में रेत का अवैध भंडारण देखा जा सकता है। वहीं विभिन्न सरकारी एवं निजी निर्माण स्थलों पर भी बिना वैध अनुमति लाई गई रेत का उपयोग किए जाने के आरोप लगाए जा रहे हैं।जानकारी के अनुसार जुन्नारदेव के एसडीएम ने 11 मई



2026 को पत्र क्रमांक 1455 जारी कर रेत चोरी रोकने के लिए संबंधित विभागों को निर्देश दिए थे। आदेश के तहत राजस्व, खनिज, वन एवं परिवहन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की इयूटी कुआं-बादला तिराहे सहित प्रमुख मार्गों पर लगाई गई थी, ताकि अवैध परिवहन पर प्रभावी निगरानी रखी जा सके।

हालांकि स्थानीय लोगों का कहना है कि लिखित आदेश जारी होने के बाद भी अवैध रेत का

परिवहन लगातार जारी है। इससे यह सवाल उठ रहे हैं कि तेनात अमला रेत चोरी रोकने में असफल क्यों साबित हो रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि प्रशासनिक निगरानी के बावजूद रेत से भरे वाहन क्षेत्र में बेखोफ आवाजाही कर रहे हैं, जिससे कार्रवाई की प्रभावशीलता पर प्रश्नचिह्न लग रहे हैं।स्थानीय नागरिकों का दावा है कि तहसीलदार के बंगले और तहसील कार्यालय के बीच मुख्य मार्ग पर चल रहे निर्माण कार्यों सहित भारिया ढाना में स्थित आईटीआई कॉलेज, सदीपनी स्कूल परिसर में बन रहे कन्या छात्रावास, पुराने मिडिल स्कूल परिसर में निर्माणधीन छात्रावास, मंगल भवन तथा अन्य निर्माण स्थलों पर भी कथित रूप से अवैध रूप से लाई गई रेत का उपयोग किया जा रहा है। हालांकि इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

एक माह से बंद घरों में चोरी करने वाला गिरोह गिरफ्तार पांच आरोपी दबोचे, चोरी का सामान बरामद



हरिभूमि न्यूज » दमुआ

थाना दमुआ पुलिस ने बंद मकानों में चोरी की वारदातों का खुलासा करते हुए पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी का सामान एवं वारदात में प्रयुक्त दो मोटरसाइकिल जब्त की हैं। आरोपियों को न्यायालय में पेश कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।

पुलिस के अनुसार 7 जुलाई 2026 को करमोहनीबंधी घोड़ावाड़ी निवासी नईम कुरैशी (42) ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह ठेकेदारी का कार्य करते हैं और कृषि कार्य के लिए लगभग एक माह से अमरवाड़ा के ग्राम सोनपुर जागीर गए हुए थे। लौटने पर उन्होंने देखा कि घर

के पीछे स्थित स्टोर रूम का दरवाजा खोलकर अज्ञात चोर पानी भरने का टिल्लू पंप, लोहे की कढ़ाई, पुराना लोहे का सिलबट्टा तथा कुलर का एजॉस्ट फैन चोरी कर ले गए हैं।

मोहल्ले के लोगों से पूछताछ में यह भी जानकारी मिली कि इसी अवधि में सुरेश राव के घर से भी टिल्लू पंप चोरी हुआ था।प्राथम्य की शिकायत पर थाना दमुआ में अपराध क्रमांक 136/26 दर्ज कर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 331(4) एवं 305(ए) के तहत मामला कायम कर विवेचना शुरू की गई। पुलिस ने मुखबि्र तंत्र सक्रिय कर संदेहियों की तलाश शुरू की। पूछताछ के दौरान सदीप धुर्वे, शैलेन्द्र हनोते,

इधर भी रखे नजर, हटके है खबर... कृषि विभाग पर वसूली के गंभीर आरोप, शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं?

हरिभूमि न्यूज, छिंदवाड़ा। शहर में कृषि आदान सामग्री विक्रेताओं के बीच इन दिनों यह चर्चा जोरों पर है कि कृषि विभाग के कुछ अधिकारियों पर कथित रूप से निरीक्षण के नाम पर अतैध वसूली किए जाने के आरोप लग रहे हैं। व्यापारियों का दावा है कि चलने वाली दुकानों से 5,000 से 10,000 तक की मांग की जाती है, जबकि कम कारोबार वाली दुकानों से भी कथित रूप से राशि मांगी जाती है। आरोप है कि राशि नहीं देने पर पीसी दिखाने, माल जफ्त करने, गोदाम सील करने और प्रकरण दर्ज करने की चेतावनी दी जाती है। कुछ व्यापारियों का यह भी कहना है कि कथित तौर पर कुछ अधिकारी कार्यालय के बजाय अवकाश के दिन निजी स्थानों पर बुलाकर लेन-देन करने का दबाव बनाते हैं। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है।बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले इन कथित मामलों की शिकायत जिला उप संचालक कृषि कार्यालय में भी की गई थी, लेकिन शिकायत पर अब तक किसी ठोस कार्रवाई या जांच की जानकारी सामने नहीं आई है। इससे शिकायतकर्ताओं में नाराजगी और असंतोष बढ़ रहा है। यदि लगाए गए आरोप सही पाए जाते हैं तो यह मामला न केवल विभागीय कार्यप्रणाली बल्कि किसानों और व्यापारियों के भरोसे पर भी गंभीर प्रश्नचिह्न खड़ा करता है। अब सभी की नजर इस बात पर है कि संबंधित अधिकारी इन आरोपों पर क्या स्पष्टीकरण देते हैं और सक्षम प्रशासन निष्पक्ष जांच कर क्या कार्रवाई करता है।



समाजसेवी दयानंद ने कमानिया गेट के पास भरे गड्ढे



े छिंदवाड़ा। कमानिया गेट के पास विगत लंबे समय से जहाँ-तहाँ बड़े-बड़े गड्ढे हो जाने के कारण बाजार में आने वाले आम नागरिकों के वाहन इन गड्ढों में फँसने एवं बारिस में जलभराव के कारण पैदल चलने वाले लोगों के इसमें गिर रहे थे, जिसे लेकर स्थानीय नागरिकों में आक्रोश व्याप्त था और उन्होंने इस संबंध में निगम प्रशासन को भी अवगत करवाया परंतु ये गड्ढे नहीं भरे गये, जबकि यह शहर का अत्यंत ही व्यस्ततम मार्ग है, जहाँ से प्रतिदिन हजारों लोग आवागमन करते हैं । समाजसेवी दयानंद ने आये दिन हो रही घटनाओं एवं प्रतिदिन इसी स्थान निकलने वाली रेलियों को देखते हुये प्रशासन का ध्यानाकर्षण करने के लिये स्वयं इन गड्ढो भरा हुए व नगर निगम प्रशासन से मांग की है कि फक्कड़ा चैक से कमानिया गेट तक शीघ्र मार्ग बनवाया जावे जिससे आमजन के होने वाली घटनाओं पर रोक लग सके ।

सिविल अस्पताल हरई में सफलता की कहानी: सर्पदंश से 4 अनमोल जीवन बचाए गए



हरई। विकासखंड हरई में अलग-अलग स्थानों पर सर्पदंश की चार गंभीर घटनाएँ सामने आईं। इनमें ग्राम रातामाटी (मैसा खुर्द) की 17 वर्षीय ज्योति उड्डके (पिता सुरेश उड्डके), बादकाषाण के 17 वर्षीय वीरेंद्र, ग्राम बुढ़ेना चट्टी की श्रीमती डमरू अहिरवार, तथा ग्राम नान्दना पिपरिया के 17 वर्षीय आकाश उड्डके (पिता महेश उड्डके) सर्पदंश का शिकार हुए।घटना की सूचना मिलते ही **CHO, ASHA**, पटवारी, सचिव, पुलिस विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग की टीम तत्काल सक्रिय हो गई। ज्योति उड्डके को **CHO** द्वारा अपनी निजी गाड़ी से तुरंत अस्पताल पहुँचाया गया। श्रीमती डमरू अहिरवार को पटवारी देवेन्द्र के सहयोग से सुरक्षित अस्पताल पहुँचाया गया, जबकि आकाश उड्डके को पटवारी आकाश एवं रोहित के सहयोग से समय पर अस्पताल लाया गया। सभी मामलों में विभिन्न विभागों के उत्कृष्ट समन्वय और त्वरित कार्रवाई से मरीजों को बिना विलंब के उपचार उपलब्ध कराया गया।अस्पताल में चिकित्सकों द्वारा समय पर एंटी स्नेक वेनम (**ASV**) सहित आवश्यक उपचार प्रारंभ किया गया। **CHO, ASHA**, पटवारी, सचिव, पुलिस विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग की संजगता, समय पर रेफरल और बेहतर समन्वय के कारण चारों मरीजों की जान बचाई जा सकी तथा वे स्वस्थ होकर लौटे। अपने घर हरई बी एस ओ डॉक्टर रानी वर्मा व समस्त स्टाफ के अथक प्रयास से मिली सफलता। सर्पदंश एक मेडिकल इमरजेंसी है। झाड़ू-फूंक, तंत्र-मंत्र या घरेलू उपचार में समय बिचकृत न गंवावें। सर्पदंश होने पर तुरंत नजदीकी सरकारी अस्पताल पहुँचें। समय पर दिया गया एंटी स्नेक वेनम (**ASV**) और उचित उपचार ही जीवन बचाता है।

पिपला हादसे के बाद प्रशासन सख्त, अतिक्रमणकारियों में मचा हड़कंप साहब जी! सौंसर में अतिक्रमण पर कब होगी कार्यवाही

हरिभूमि न्यूज » सौंसर

हाल ही में पिपला में बेलगाम वाहन की चपेट में आने से 7 लोगों के घायल होने की दर्दनाक घटना के बाद जिला प्रशासन ने सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को लेकर सख्त रुख अपना लिया है।

इस घटना से सबक लेते हुए पिपला पुलिस और नगर परिषद की संयुक्त टीम ने मुख्य मार्गों और बस स्टैंड परिसर से अतिक्रमण हटाने की बड़ी कार्रवाई की है। इस अभियान के तहत सड़क किनारे लगे अस्थाई ठेलों, दुकानों और अन्य अवरोधों को हटाया गया, ताकि आवागमन सुगम हो सके। इस संयुक्त कार्रवाई के दौरान मुख्य नगर पालिका अधिकारी



डी.पी. साहू ने स्पष्ट किया कि नागरिकों की सुरक्षा सर्वोपरि है। उन्होंने अतिक्रमणकारियों को सख्त चेतावनी दी कि यदि भविष्य में दोबारा सड़क पर अतिक्रमण किया गया, तो संबंधितों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई के

दौरान चौकी प्रभारी रवि बड्ढी सहित नगर परिषद का पूरा अमला मुस्तैद रहा। प्रशासन के इस कड़े कदम से बस स्टैंड और मुख्य मार्गों पर यातायात व्यवस्था में सुधार तो दिखाई दिया, लेकिन साथ ही अवैध कब्जाधारियों में हड़कंप मच गया है।

सुलग रही मांग: कब हटेगा बस स्टैंड और मुख्य मार्गों का अतिक्रमण?

पिपला ना वार की घटना के बाद अब सौंसर के जागरूक नागरिकों और स्थानीय निवासियों ने भी शहर के मुख्य मार्गों से अतिक्रमण हटाने की मांग को तेज कर दिया है। वर्तमान में सौंसर बस स्टैंड, यात्री प्रतीक्षालय, गुरुदेव सेवा आश्रम के सामने, साप्ताहिक बाजार और चौपाटी क्षेत्र में दुकानदरारों द्वारा किए गए अवैध कब्जों के कारण राहगीरों का चलना दूषार हो गया है।विशेष रूप से बस स्टैंड और श्री गुरुदेव सेवा आश्रम के सामने फैले अतिक्रमण से जाई क्रमांक 15, गुरुदेव कॉलोनी, मोहगांव और आसपास की कॉलोनियों में जाने वाले लोगों, स्कूली बच्चों और महिलाओं को हर दिन भारी जद्दोजहद करनी पड़ती है। गुरुदेव कॉलोनी वासियों ने नया प्रशासन से मांग की है कि न केवल अतिक्रमण हटया जाए, बल्कि इस क्षेत्र का सौंदर्यीकरण भी किया जाए। सूत्रों के अनुसार, नगर पालिका प्रशासन अब सौंसर में भीअतिक्रमणकारियों पर कनेकल करने की तैयारी कर रहा है। बस स्टैंड क्षेत्र के चिह्नित अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी किए जाने की खबर है। अब देखना यह है कि क्या प्रशासन अपने इस अभियान में सफल हो पाता है, या यह अतिक्रमणकारी फिर से अपनी जगह जमा लेंगे। शहर की जनता को अब ठोस और स्थाई कार्रवाई का इंतजार है।



पांच साल में नहीं बना आमला और नदुढाना की पुलिया

7 गाँवों हजारों ग्रामीण हो रहे परेशान, छात्र छात्राएं जान जोखिम में डालकर आवागमन को मजबूर ग्रामीण

हरिभूमि न्यूज़ ॥सौसर

योजनाए जहाँ ग्रामीण क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास और बुनियादी सुविधाओं सड़क, बिजली और पानी को हर घर तक पहुँचाने का दावा करती है, वहीं सौसर क्षेत्र की जमीनी हकीकत इन दावों की पोल खोल रही है।

आमला से नदुढाना के बीच स्थित एक पुलिया पिछले 5 वर्षों से अधूरे निर्माण की भेंट चढ़ी हुई है, जिसके कारण 7 गाँवों के हजारों ग्रामीण ओर बच्चे अपनी जान जोखिम में डालकर आवागमन करने को मजबूर हैं।

लगभग 5 वर्ष पूर्व, पुरानी पुलिया को तोड़कर नई पुलिया के निर्माण का कार्य शुरू किया गया था। उम्मीद थी कि जल्द ही ग्रामीणों को आवागमन की बेहतर सुविधा मिलेगी, लेकिन पांच साल बीत जाने के बाद भी यह पुलिया आज तक अधूरी पड़ी है। निर्माण कार्य की गति इतनी धीमी है कि ग्रामीणों को



विकास केवल कागजों पर ही नजर आता है। स्थानीय युवा नेता अल्केश बागड़े ने बताया कि ठेकेदार की लापरवाही और विभागीय उदासीनता के कारण पिछले 5 वर्षों से यहाँ का जनजीवन अस्त-व्यस्त है।

पुलिया निर्माण के दौरान ठेकेदार ने वैकल्पिक मार्ग के रूप में एक अस्थायी 'अप्रोच पुलिया' बनाई थी, जो अब बारिश के कारण पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी है। हालात इतने खराब हैं कि अब इस मार्ग से चार



पहिया तो दूर, दोपहिया वाहन निकालना भी जान जोखिम में डालने जैसा है। सबसे बड़ी समस्या स्कूली छात्र-छात्राओं और मरीजों के लिए पैदा हो गई है। बारिश के दिनों में स्कूली बच्चों

का कहना है कि ऐसी स्थिति में मरीज का 'भगवान ही मालिक' है। युवा ग्रामीण अल्केश बागड़े ने चर्चा के दौरान बताया कि कुछ दिन पूर्व जब आमला में महामाहिम का दौरा प्रस्तावित था, तब आनन-फानन में काम को गति देने का दिखावा किया गया था। लेकिन जैसे ही दौरा संपन्न हुआ, निर्माण कार्य पुनः बंद कर दिया गया। यह प्रशासनिक संवेदनहीनता का जीता-जागता उदाहरण है।

ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही स्वीकृत पुलिया और क्षतिग्रस्त अप्रोच मार्ग का निर्माण कार्य शुरू नहीं किया गया, तो वे संबंधित विभाग और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ उग्र जन आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। 7 गाँवों के निवासियों ने प्रशासन से मांग की है कि उनकी समस्या को गंभीरता से लिया जाए ताकि भविष्य में किसी बड़ी अनहोनी को टाला जा सके।

वार्ड 9 एवं वार्ड 1 में निर्माण कार्य का भूमिपूजन



जुन्नारदेव : वार्ड क्रमांक 09 एवं वार्ड क्रमांक 1 में पेटेर ह्लाक स्थापन वार्ड क्रमांक 1 के कर्मा चौक पर कार्य राम मंदिर के सामने किया जाएगा जिसका भूमि पूजन कार्यक्रम आज संपन्न हुआ। इस निर्माण कार्य की लागत 6.83 लाख रु में होगा है साथ ही वार्ड क्रमांक एक की लागत 10 लाख 63 है है।जिसका भूमिपूजन अध्यक्ष नगर पालिका रमेश सालोडे, उपील समिति सदस्य सभापति संजय जैन नीता शरद कुरोलिया (लोक निर्माण विभाग) अमित कुमार यादव सभापति वार्ड क्रमांक पार्षद वार्ड क्र. एक एक श्रीमती लता देवेन्द्र टांडेकर 09 की गरिमामय उपस्थिति में सम्पन्न हुआ। इस अवसर पर मुख्य नगर पालिका अधिकारी श्रीमती नेहा धुर्वे, राजेश श्रीवास्तव, विशेष चरसिया,उपपंजी ठेकेदार मेसर्स भूषण अरोरा समस्त वार्डवसी भाजपा कार्यकर्ता एवं पार्षद गण उपस्थित थे।

यूनिफॉर्म सिविल कोड विषय पर निबंध प्रतियोगिता संपन्न आज, भाषण प्रतियोगिता और पुरस्कार वितरण



जुन्नारदेव : यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) एक महत्वपूर्ण एवं समसामयिक विषय के रूप में चर्चा का केंद्र बना हुआ है। विद्यार्थियों में विधिक जागरूकता,नैतिक चिंतन तथा अभिव्यक्ति कोशिल का विकास करने के उद्देश्य से पंडित रविशंकर शुक्ल स्कूल में यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) विषय पर निबंध प्रतियोगिता गुरुवार को संपन्न हुई। आज शुक्रवार 2:00 बजे से भाषण प्रतियोगिता आयोजित होगी। प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया जाएगा। साथ ही प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों को प्रशस्ति-पत्र (प्रमाण-पत्र) प्रदान किए जाएंगे।कार्यक्रम के समापन अवसर पर विधि विशेषज्ञों, अधिकारताओं एवं विशिष्ट अतिथियों द्वारा प्रेरक उद्बोधन होगा ।

अग्नि सुरक्षा एवं आपातकालीन निकासी अभ्यास संपन्न

परासिया :- संत चवारा नेशनल एकेडमी में आज आपातकालीन स्थितियों से निपटने और सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए एक 'अग्नि सुरक्षा एवं निकासी अभ्यास' (फायर सेफ्टी और इवैक्यूएशन ड्रिल) का सफल आयोजन किया गया।इस विशेष मौक़ ड्रिल का नेतृत्व श्री अंकित सोलंकी ने किया। उनके मार्गदर्शन में सभी शिक्षकों और छात्र कैबिनेट (Student Cabinet) के सदस्यों ने सक्रिय भूमिका निभाते हुए पूरी सुरक्षीदी के साथ पूरे स्कूल परिसर को सुरक्षित और व्यवस्थित तरीक़े से खाली कराया। इस दौरान विद्यार्थियों को आपातकालीन निकास मार्गों और संकट के समय शान्त रहने के तरीकों की जानकारी दी गई।अभ्यास के समापन पर विद्यालय के प्राचार्य फ़ादर जैसन ने सभी छात्रों और स्टाफ़ के अनुशासन, सतर्कता और बेहतरीन तालमेल की सराहना की। उन्होंने इस सफल आयोजन के लिए अंकित सोलंकी, शिक्षक वर्ग और छात्र नेताओं को बधाई देते हुए कहा कि सुरक्षित माहौल के लिए ऐसे अभ्यास बेहद जरूरी हैं ।



सभाकक्ष का विधायक वाल्मीक ने किया लोकार्पण, जीरामजी की दी जानकारी

हरिभूमि न्यूज़ ॥परासिया

जनपद परासिया में आज दिनांक 09 जुलाई 2026 को एक और नए सभाकक्ष का लोकार्पण विधायक सोहन लाल वाल्मीकि द्वारा किया गया । वहीं जी राम जी (पनरंग) की जानकारी दी गई।गुरुवार को जनपद परासिया में विधायक सोहन वाल्मीकि की उपस्थिति में दो कार्यक्रम संपन्न हुए ।

विधायक ने एक ओर जहां लगभग 200 लोगों के बैठने की क्षमता वाले सभाकक्ष का लोकार्पण किया गया , वहीं केंद्र सरकार द्वारा मनरंगा योजना का नाम बदल कर विकसित भारत की राम जी करने के बाद इस पुनः चालू किया गया । जिस पर एक संवाद कार्यक्रम भी हुआ । जिसमें योजना अधिकारी सरिता शेंडे के द्वारा विस्तृत जानकारी दी गई । वहीं संवाद के



दौरान मौजूद जनपद सदस्यों , सरपंचो ने सवाल भी पूछे , जिसका जवाब बड़ी सहजता के साथ अधिकारी ने दिया । अधिकारी श्रीमती शेंडे ने बताया , कि इस योजना में हितग्राहियों को साल में 125 दिन का ग्राम में ही रोजगार दिया जाएगा । काम करने के इच्छुक व्यक्ति को लिखित या मौखिक आवेदन करना होगा । Job कार्ड होना अनिवार्य है । जिनके पास जांब कार्ड हैं , उन्हें ई के वाय सी कराना अनिवार्य

है । नए जांब कार्ड पंचायत से बनाए जाएंगे । सी ई ओ वर्षा झारिया ने बताया , कि शिपी एप्प के माध्यम से ग्रामीणों को मिल सकेगी । विधायक सोहन वाल्मीकि ने पूछा , कि जिन्हें कार्य नहीं मिलेगा क्या उन्हें बेरोजगारी भत्ता देने का कोई प्रावधान हैं ? जिस पर बताया गया की कार्य नहीं मिलने की स्थिति में कार्ड धारक को आवेदन के बाद 16 वें दिन से निर्धारित दैनिक वेतन 300/- रूपये पर 0.05 की दर से भत्ता देने का प्रावधान हैं ।

मूंग की सरकारी खरीदी में आ रही दिक्कतों और सरकार द्वारा तय किए गए कठिन मापदंडों के विरोध में आज भारतीय किसान संघ सौसर ने मोर्चा खोल दिया। जबलपुर प्रांत के आह्वान पर प्रदेश भर की तहसील कार्यालयों में हुए प्रदर्शन के क्रम में, आज सौसर में भी भारतीय किसान संघ के पदाधिकारियों और सैकड़ों किसानों ने एकजुट होकर अनुविभागीय राजस्व अधिकारी को ज्ञापन सौंपा।

इस दौरान किसानों ने प्रदेश सरकार की नीति पर तीखे सवाल उठाए। भारतीय किसान संघ के पदाधिकारियों का कहना है कि सरकार द्वारा मूंग खरीदी के लिए निर्धारित किए गए मापदंड पूरी तरह से किसान विरोधी हैं। इन जटिल नियमों के चलते बड़ी संख्या में किसान अपना पंजीयन कराने में असमर्थ हैं, जिससे उनकी उपज को सरकारी दर पर बेचना मुश्किल हो गया है। संघ की प्रमुख मांग है कि



इन मापदंडों को तत्काल सरल किया जाए और राज्य सरकार सभी पंजीकृत किसानों से उनकी शत-प्रतिशत उपज की खरीदी सुनिश्चित करे। किसानों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर शीघ्र निर्णय नहीं लिया गया, तो वे अपने आंदोलन को और अधिक तीव्र करेंगे। ज्ञापन सौंपने के दौरान

भारतीय किसान संघ के तहसील अध्यक्ष आशीष पराड़कर, तहसील मंत्री पवन हिंगवे, जिला उपाध्यक्ष रविशंकर धुर्वे, एडवोकेट प्रदीप पराड़कर, ज्ञानेश्वर पराड़कर, कमलेश पगारे, भागचंद कामटे, अनिल गोरे, नानु खडे और गणपति किनकर सहित बड़ी संख्या में किसान उपस्थित थे।

विधायक और तहसीलदार से की शिकायत : किसानों का आरोप अवैध तरीके से काटा निस्तारी रास्ता

हरिभूमि न्यूज़ कटंगी।

कटंगी से पाथरवाड़ा मुख्य सड़क मार्ग पर अर्जुननाला और पाथरवाड़ा गांव की सीमा पर निस्तारी रास्ता काटे जाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। स्थानीय किसानों ने आरोप लगाया है कि प्लान्टिंग करने के उद्देश्य से मनोज गुप्ता नामक व्यक्ति ने जेसीबी मशीन से दशकों पुराने रास्ते को काट दिया है। इससे किसानों के लिए अपने खेतों तक जाना मुश्किल हो गया है। गत दिवस किसानों ने 29 जून को ही तहसीलदार और क्षेत्रीय विधायक गौरव सिंह पारधी से लिखित शिकायत की थी, लेकिन 10 दिन बीत जाने के बाद भी जांच नहीं हुई है। किसानों के अनुसार अर्जुननाला और पाथरवाड़ा गांव की सीमा पर पिछले कई दशकों से 12 फीट चौड़ी निस्तारी सड़क थी। इसी रास्ते से दर्जनों किसान अपने खेतों तक



आते-जाते थे। किसानों का आरोप है कि 28 जून की रात को मनोज गुप्ता ने प्लान्टिंग करने के लिए जेसीबी मशीन की मदद से इस रास्ते को काट दिया। सुबह जब किसान खेतों पर पहुंचे तो रास्ता बंद मिला। गुरुवार को किसानों ने मौके पर इकट्ठा होकर अपनी परेशानी साझा की। रास्ता कटने के अगले दिन 29 जून को प्रभावित किसानों ने कटंगी तहसीलदार और क्षेत्रीय विधायक गौरव सिंह पारधी को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की थी। किसानों का कहना है कि तहसीलदार ने शिकायत मिलने पर



राजस्व निरीक्षक को जांच के आदेश दिए थे, लेकिन 09 जुलाई तक कोई भी अधिकारी मौके पर जांच के लिए नहीं पहुंचा। इससे किसानों में नाराजगी है। इस मामले में हल्का पटवारी ओम प्रकाश राहंगडाले ने बताया कि पाथरवाड़ा और अर्जुननाला दोनों गांव के पटवारी ने संयुक्त रूप से भूमि का सीमांकन किया था। सीमांकन के दौरान देव बोपचे और मनोज गुप्ता दोनों को उनकी जमीन की सीमा बताई गई थी। पटवारी के अनुसार देव बोपचे ने अपनी निर्धारित भूमि से कुछ

अधिक हिस्से में निर्माण कर लिया है। वहीं मनोज गुप्ता को भी मेड़ नहीं काने की सलाह दी गई थी। बावजूद इसके रास्ता काट दिया गया। किसानों ने कहा कि यह निस्तारी रास्ता है और इसे काटना अवैध है। मानसून का समय है और खेतों में काम शुरू हो गया है। रास्ता बंद होने से बीज, खाद और दवाई खेतों तक नहीं पहुंच पा रही है। फिलहाल यह मामला अब विवादों में रलझ गया है। किसानों को उम्मीद है कि विधायक और प्रशासन के हस्तक्षेप से जल्द उन्हें राहत मिलेगी।

पशु चिकित्सकों की कमी से बड़ी किसानों की चिंता, मोहड़री अस्पताल में तत्काल स्टाफ तैनाती की मांग

जनपद सदस्य एवं कृषि समिति सभापति ने कलेक्टर के नाम सौंपा ज्ञापन, वर्षा ऋतु में पशुओं के उपचार को लेकर जताई चिंता
हरिभूमि न्यूज़ लॉजी ।



लांजी जनपद पंचायत क्षेत्र के मोहड़री पशु चिकित्सालय में चिकित्सकीय स्टाफ की कमी को लेकर किसानों और पशुपालकों की चिंता अब प्रशासन तक पहुंच गई है। जनपद पंचायत सदस्य एवं कृषि समिति के सभापति इंजी. टुमनलाल घोरमारे ने कलेक्टर के नाम अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) लांजी को ज्ञापन सौंपकर मोहड़री पशु चिकित्सालय और नेवरवाही पशु औषधालय में पर्याप्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों की शीघ्र पदस्थापना की मांग की है। उनका कहना है कि

समय रहते व्यवस्था नहीं की गई तो हजारों पशुपालकों को गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ज्ञापन में बताया गया है कि लांजी क्षेत्र आदिवासी एवं कृषि प्रधान है, जहां अधिकांश परिवार कृषि और पशुपालन पर अपनी आजीविका के लिए निर्भर हैं। मोहड़री पशु चिकित्सालय लगभग 25 से 30 गांवों के हजारों किसानों और पशुपालकों को पशु चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराता है। लेकिन हाल ही में अधिकारियों एवं

कर्मचारियों के स्थानांतरण के बाद यहां स्टाफ की कमी की स्थिति बन गई है। वहीं नेवरवाही पशु औषधालय में भी पर्याप्त कर्मचारियों का अभाव बना हुआ है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में पशुओं का समय पर उपचार प्रभावित हो रहा है। इंजी. टुमनलाल घोरमारे ने ज्ञापन में उल्लेख किया है कि वर्षा ऋतु के दौरान पशुओं में संक्रामक रोग फैलने की आशंका सामान्य दिनों की तुलना में अधिक रहती है। यदि चिकित्सकीय सेवाएं प्रभावित

होती हैं तो पशुधन को व्यापक क्षति पहुंच सकती है, जिसका सीधा आर्थिक नुकसान किसानों को उठाना पड़ेगा। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि स्थानांतरित अधिकारियों एवं कर्मचारियों के स्थान पर तत्काल वैकल्पिक पदस्थापना की जाए, ताकि पशु चिकित्सालय की सेवाएं निबांध रूप से संचालित हो सकें। साथ ही नेवरवाही पशु औषधालय में भी आवश्यक स्टाफ की शीघ्र तैनाती सुनिश्चित की जाए। जनपद सदस्य ने कहा कि पशुधन ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसानों की आय का महत्वपूर्ण आधार भी। ऐसे में जनहित एवं कृषक हित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए प्रशासन को इस मामले में तत्काल निर्णय लेना चाहिए, जिससे क्षेत्र के हजारों पशुपालकों को समय पर उपचार सुविधा मिल सके और वर्षा ऋतु में संभावित संकट से पशुधन की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।

संबल योजना बनी सहारा: मृतक श्रमिक के परिवार को मिली दो लाख रुपये की सहायता राशि

हरिभूमि न्यूज़ लॉजी । मध्यप्रदेश शासन की जनकल्याणकारी मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजना के तहत लांजी के वार्ड क्रमांक 9 निवासी स्वर्गीय देवेश तिड़के के निधन के बाद उनके परिवार को आर्थिक संबल प्रदान किया गया। योजना के अंतर्गत स्वीकृत दो लाख रुपये की अनुग्रह सहायता राशि मृतक की पत्नी श्रीमती गीता तिड़के को एक कार्यक्रम के दौरान प्रदान की गई। सहायता राशि का वितरण लांजी विधायक राजकुमार करहि के उपस्थिति में नगर परिषद अध्यक्ष श्रीमती रेखा कालबेले, उपाध्यक्ष संदीप रामटेककर तथा वार्ड क्रमांक 9 के पार्षद एवं सभापति के हाथों किया गया। इस अवसर पर विधायक ने कहा कि संबल योजना असांगठित श्रमिक परिवारों के लिए महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच है। परिवार के मुखिया की असामयिक मृत्यु के बाद मिलने वाली आर्थिक सहायता कठिन परिस्थितियों में परिवार को राहत देने का कार्य करती है।

कार्यक्रम के दौरान वार्डवासियों ने विधायक के समक्ष क्षेत्र की अनुरोध समक्याएं भी रखीं। विधायक श्री करहि ने नागरिकों को आश्वासन दिया कि जनहित से जुड़े सभी मामलों का प्राथमिकता के आधार पर निराकरण कराया जाएगा तथा संबंधित विभागों को आवश्यक निर्देश दिए जाएंगे। इस अवसर पर भाजपा मंडल अध्यक्ष आलोक चौरसिया, गौरव बैस, नवीन रामटेककर, महिला मोर्चा की प्रेमा सिसोदिया, श्रीमती श्यामा मुरकट सहित वार्ड के अनेक गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। कार्यक्रम के पश्चात जगप्रतिनिधियों एवं पार्टी पदाधिकारियों की एक अनौपचारिक बैठक भी आयोजित की गई, जिसमें संगठनात्मक गतिविधियों और पार्टी द्वारा चलाए जा रहे डिजिटल सर्विफिकेट अभियान सहित विभिन्न विषयों पर विचार-विमर्श किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक पहुंचाना और नागरिकों की समस्याओं का समाधान सुनिश्चित करना रहा।

मालू की हत्या कर शव के टुकड़े कुएं में फेंकने वाले दो आरोपी गिरफ्तार, दो फरार

हरिभूमि न्यूज़ वारासिवनी। खैरलांजी वन परिक्षेत्र अंतर्गत भालू की निर्मम हत्या कर उसके शव के टुकड़े कर कुएं में फेंकने के मामले में वन विभाग को बड़ी सफलता मिली है। विभाग ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय से रिमांड प्राप्त की है, जबकि दो अन्य आरोपी अभी फरार हैं जिनकी तलाश जारी है। जांच में सामने आया कि आरोपियों ने जंगली सुअर के शिकार के लिए खेत में अवैध रूप से करंट बिछाया था, जिसकी चपेट में एक नर भालू आ गया और उसकी मौत हो गई। इसके बाद आरोपियों ने साक्ष्य छिपाने और कथित तांत्रिक क्रियाओं में उपयोग के उद्देश्य से भालू का कलेजा और नाखून निकालने का प्रयास किया तथा शव के कई टुकड़े कर उन्हें कुएं में फेंक दिया।उल्लेखनीय है कि तीन दिन पूर्व भंडारबोड़ी और पीपरटोला की सीमा स्थित एक खेत के कुएं से भालू के शव के कई टुकड़े बरामद हुए थे। प्रारंभिक जांच में वन विभाग ने इसे निर्मम हत्या का मामला मानते हुए जांच शुरू की थी। विवेचना के आधार पर वन विभाग ने क्षेत्र के निवासी सुरेंद्र पिता हरिराम गोंड उम्र 40 वर्ष निवासी पिपरटोला भंडारबोड़ी और छबिलाल पिता टीकाराम उईके उम्र 38 वर्ष निवासी पिपरटोला भंडारबोड़ी को गिरफ्तार किया है। दोनों के विरुद्ध वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत शेड्यूल 1 की सूची क्रमांक 18 स्लांथ बिबर भालू के तहत मामला दर्ज किया गया है। फरार आरोपियों की तलाश जारी है तथा वन विभाग पूरे प्रकरण की विस्तृत जांच कर रहा है।



बच्चों को दिया अनुशासन और सुनागरिकता का संदेश जिला शिक्षा अधिकारी श्रीमती धनश्री जैन का स्काउट गाइड कैंप में आकस्मिक निरीक्षण

हरिभूमि न्यूज़ वारासिवनी। भारत स्काउट गाइड राज्य मुख्यालय भोपाल के निर्देशानुसार जिला प्रशिक्षण केंद्र वारासिवनी में पांच दिवसीय 'राज्य पुरस्कार स्काउट गाइड जांच शिविर' का गरिमापूर्ण आयोजन किया जा रहा है। 6 जुलाई से शुरू हुए इस शिविर के तीसरे दिन जिले की नवनियुक्त जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ) श्रीमती धनश्री जैन ने आकस्मिक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। प्रशिक्षण केंद्र प्रांगण में प्रथम आगमन पर स्काउट गाइड के सदस्यों द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी श्रीमती जैन को 'गाइड ऑफ ऑनर' दिया गया। इसके पश्चात स्कार्फ पहनाकर एवं 'जनरल सैल्यूट' के साथ तालीम स्वागत किया गया। इस अवसर पर श्रीमती जैन द्वारा परिसर में वृक्षारोपण के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण और प्रकृति के सौंदर्यकरण का संदेश दिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने केंद्र के सभी कक्षों का बारीकी से अवलोकन किया और प्रशिक्षण ले रहे बच्चों से सीधे बातचीत कर उनका उत्साहवर्धन किया। इस मौके पर जिला



परियोजना समन्वयक मोहित डहरिया द्वारा भी स्काउट गाइड को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। 10 जुलाई तक चलने वाले इस राज्य स्तरीय जांच शिविर में विभिन्न जिलों से कुल 80 स्काउट गाइड हिस्सा ले रहे हैं। इसमें मेजबान बालाघाट जिले की भागीदारी सर्वाधिक रही। आंकड़ों के अनुसार शिविर में बालाघाट से 41, भोपाल से 16, जबलपुर से 14 और विदिशा से 06 स्काउट गाइड सम्मिलित हुए हैं। शिविर के दौरान जिला संघ बालाघाट के कोषाध्यक्ष भोजेंद्र चौधरी ने जिला शिक्षा अधिकारी श्रीमती जैन का हृदय की अनंत गहराइयों से स्वागत किया। उन्होंने अपने स्वागत भाषण में केंद्र के पुनर्जीवित होने की

संघर्ष गाथा को साझा करते हुए कहा कि आप नई ऊर्जा और उत्साह के साथ पीएससी उत्तीर्ण कर शिक्षा के क्षेत्र में अपनी सेवाएँ दे रही हैं, जो हमारी बालिकाओं के लिए एक बड़ी प्रेरणा है।

श्री चौधरी ने कहा कि हमारा यह विद्यालय परिसर पूर्व में सांदीपनी में स्थानांतरित हो जाने के कारण पूरी तरह जर्जर और जीर्ण-शीर्ण हो चुका था। लेकिन विगत तीन वर्षों के भीतर वारासिवनी नगर की स्थानीय जनता, शिक्षकों, बालाघाट जिले के नागरिकों और शिक्षा विभाग के सामूहिक जनसहयोग व व्यक्तिगत प्रयासों से इस भवन को दोबारा सुधारा गया है, जो अब स्काउट-गाइड और योग के लिए समर्पित है। यह इस केंद्र की बहुत बड़ी उपलब्धि है कि पहली बार भोपाल से भी बच्चे यहाँ प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए आए हुए हैं। आपके कुशल नेतृत्व में हमारी यही आकांक्षा है कि यह केंद्र प्रशिक्षण का ही नहीं, बल्कि राष्ट्रीय स्तर का सबसे बेहतरीन प्रशिक्षण केंद्र बनकर उभरे।



